



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 1993/भाद्र 8, 1915

No. 33]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 1993/BHADRA 8, 1915

ग्रान्धा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय कार्यालय—कर्मचारी विभाग

अधिसूचना

हैदराबाद, 22 जुलाई, 1993

अधिसूचना सं. 666/3/ए-1/481:—बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रान्धा बैंक के निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक से विचार-विमर्श कर और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेते हुए ग्रान्धा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 में संशोधन करने के लिए निम्नांकित विनियम बनाते हैं।

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: (1) ये विनियम ग्रान्धा बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम 1993 कहे जा सकते हैं।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। ग्रान्धा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम

1982 के (क) (विनियम 20 सेवा की समाप्ति) को निम्न प्रकार पढ़ा जाए:—

1 (क) विनियम 16 के उप विनियम 3 के अधीन जब बैंक इस तथ्य से संतुष्ट है कि अधिकारी का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक या अपर्याप्त है या उनकी ईमानदारी के बारे में प्रामाणिक संदेह हो या बैंक सेवा में उनको रोक रखना बैंक के हित के प्रतिकूल होगा या जब अनुशासनिक प्रक्रिया के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करना संभव या उचित नहीं है तो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक तीन महीने की नोटिस देते हुए या उसके बदले में परिलब्धियां देकर उनकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

(ख) इस उप विनियम तहत बर्खास्तगी आदेश तब तक नहीं तैयार किया जायेगा जब तक कि ऐसे अधिकारी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध बैंक को अभ्यावेदन भेजने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

(ग) उपर्युक्त उप विनियम (क) तहत अधिकारी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का निर्णय केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा लिया जायेगा।

(घ) उप विनियम (क) तहत पारित किसी आदेश के विरुद्ध अधिकारी कर्मचारी अधिमानतः 15 दिनों के अन्दर निर्देशक मंडल के पास अपील करने के लिए अधिकृत होंगे। यदि अपील स्वीकार कर लिया जाता है तो उप विनियम (क) तहत जारी आदेश निरस्त हो जायेंगे।

(ङ) अधिकारी कर्मचारी जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं और उन्हें नोटिस के बदले में तीन महीने की परीक्षणियों का भुगतान किया गया है और उनके अभ्यावेदन पर बर्खास्तगी निरस्त हो जाती है तो नोटिस के बदले में भुगतान की गयी रकम का समायोजन उस वेतन से किया जायेगा, जो उन्होंने अर्जित किया है, मानो उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की गयी थी और वे बैंक नियोजन में उसी नियम व शर्तों के आधार पर उनकी नौकरी बनी रहेगी मानो कि बर्खास्तगी आदेश पारित ही नहीं किया गया था।

(च) ऊपर के उप विनियम (क) तहत जिन अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की गयी हैं, उन्हें अनुदान, नियोजता अंशदान सहित भविष्य निधि एवं अन्य सभी ग्राह्य बकायों का भुगतान नियमानुसार की गयी सेवाओं के लिए किया जायेगा।

(घ) उपर्युक्त में से किसी बात के अंतर्निहित न होने पर विनियम 19(1) तहत अधिकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करना बैंक के अधिकार को प्रभावित करेगा।

2. अधिकारी अपनी नौकरी को छोड़ने, समाप्त करने या पदत्याग करने के अपने इरादे की लिखित रूप में पूर्व सूचना दिये बिना बैंक की नौकरी को नहीं छोड़ेंगे या समाप्त नहीं करेंगे या पदत्याग नहीं करेंगे। अपेक्षित नोटिस अवधि तीन महीने की होगी और इन विनियमों में निर्धारित अनुसार सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

परन्तु सक्षम-प्राधिकारी 3 महीने की अवधि को कम कर सकते हैं या नोटिस की आवश्यकता को माफ कर सकते हैं।

3(i) अधिकारी, जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विचाराधीन है, वे सक्षम अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना बैंक की अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे, समाप्त नहीं करेंगे या पदत्याग नहीं करेंगे और अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान या पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा दी गयी पदत्याग की सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

(ii) इस विनियम के उद्देश्य हेतु किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही स्थगित होना माना जायेगा, यदि वह निलंबित किया गया है या कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाय और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित होना समझा जायेगा।

(iii) अधिकारी जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी है, सेवानिवृत्ति की तारीख पर उनकी सेवा समाप्त होना माना जायेगा, परन्तु यह मानकर अनुशासनिक कार्यवाही जारी रहेगी कि वे सेवा में हैं और तब तक जारी रहेगी जब तक कार्यवाही समाप्त नहीं होती है और इस संबंध में अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद संबंधित अधिकारी किसी प्रकार का वेतन और/या भत्ता प्राप्त नहीं करेंगे। कार्यवाही के पूरा होने और उस संबंध में अंतिम आदेश पारित होने तक वे सी पी एफ के अपने अंशदान को छोड़ सेवानिवृत्ति लाभ की अवयगी के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

चक्का राजा राव, महा प्रबन्धक (का)

ANDHRA BANK

(A Govt. of India Undertaking)

Central Office : Staff Dept.

NOTIFICATION

Hyderabad, the 22nd July, 1993

Notification No. 666/3/A1/481.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to Amend the Andhra Bank (Officers') Service Regulations, 1982.

2. Short title and commencement : (1) These Regulations may be called the Andhra Bank Officers' Service Amendment Regulations, 1993 ;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Andhra Bank (Officers') Service Regulations, 1982 :—

(a) Regulation 20 (Termination of Service) shall read as under :—

(1) (a) Subject to sub-regulation 3 of regulation 16, where the Bank is satisfied that the performance of an officer is unsatisfactory or inadequate or there is a bona fide suspicion about his integrity or his retention in the Bank's service would be prejudicial to the interests of the Bank and where it is not possible or expedient to proceed against him as per the disciplinary procedure, the Bank may terminate his services on giving him three months' notice or emoluments in lieu thereof in accordance with the guidelines issued by the Government from time to time.

(b) Order of termination under this sub-regulation shall not be made unless such officer has been given a reasonable opportunity of making a representation to the Bank against the proposed order.

- (c) The decision to terminate the services of an Officer employee under sub-regulation (a) above will be taken only by the Chairman and Managing Director.
- (d) The officer employee shall be entitled to appeal against any order passed under sub-regulation (a) above by preferring an appeal within 15 days to the Board of Directors of the Bank. If the appeal is allowed, the order under sub-regulation (a) shall stand cancelled.
- (e) Where an officer employee whose services have been terminated and who has been paid an amount of three months emoluments in lieu of notice and on appeal his termination is cancelled, the amount paid to him in lieu of notice shall be adjusted against the salary that he would have earned, had his services not been terminated and he shall continue in bank's employment on same terms and conditions as if the order of termination had not been passed at all.
- (f) An Officer employee whose services are terminated under sub-regulation (a) above shall be paid Gratuity, Provident Fund including employer's contribution and all other dues that may be admissible to him as per rules notwithstanding the years of service rendered.
- (g) Nothing contained hereinabove will affect the Bank's right to retire an officer employee under 19(1).
- (2) An officer shall not leave or discontinue his service in the Bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue his service or resign. The period of notice required shall be 03 months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these regulations. Provided further that the competent authority may reduce the period of 03 months, or remit the requirement of notice.
- 3 (i) An officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave/discontinue or resign from his service in the bank without the prior approval in writing of competent authority and any notice or resignation given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.
- (ii) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings shall not be instituted against him and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.
- (iii) The officer against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer will not receive any pay and/or allowance after the date of superannuation. He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contributions to CPF.

CH. RAJA RAO, General Manager
(Personnel)

